

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी, 2020

विषय-जनपद मथुरा में कोसीकला के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, द्वायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4128/6-1-1/ब्र.ती.वि.प./(99)/2019 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कोसीकला के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, द्वायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के कार्य कराये जाने हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उसके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रु0 740.10 लाख (रुपये सात करोड़ चालीस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रु0 370.05 लाख (रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख पांच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रश्नगत कार्य की निविदा इंडेंडरिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों/शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यलय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 दिनांक 29 जुलाई 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उरी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। निविदाओं/पत्रों में किये गये कार्यों के सापेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

- (3) प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ आदि प्रयुक्त करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वािरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पर्यटन निदेशालय/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी आदि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अछादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन का तैयार कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य की निविदा से सम्बन्धित अभिलेख शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा तभी प्रायोजना की अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- (6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानिटरिंग) पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाय। कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्मित परिसम्पत्ति के समुचित रख-रखाव एवं अनुरक्षण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा अधिरोपित लेबों सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) प्रायोजना के अन्तर्गत कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अनुपालन का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी की होगी। प्रायोजना में दाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून 2017 के अन्तर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

आरो पी० सिंह
अधीक्षण अधिकारी

आरो पी० सिंह
अधीक्षण अधिकारी

1. यह शासनादेश प्रारम्भिकता के लिए जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रारम्भिकता के लिए साइट <http://sbasanadesh.pw.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(10) परियोजना में कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किये गये आगणन में मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा का होगा। प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों आदि प्रयुक्त करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा अधिरोपित लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजना की स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में महानिदेशक पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाविवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक पर्यटन का होगा।

आर० पी० सिन्हा काज जीव विज्ञान परिषद के कार्य हेतु कार्यकारी समिति में एक नवोदय विचारक के रूप में कार्य करेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7- 37 /दस-2020 दिनांक 13 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भूतदीय
(ए०पी० सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 21 /2020/3486(1)/41-2019-130(बजट)/2019 दिनांक तद्वत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- उपाध्यक्ष, उ०प्र० ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
- 4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा/लखनऊ।
- 7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
- 12- क्षेत्र अधिकारी, पर्यटन विभाग।
- 13- गाइडमाइल।

22/06/2021
अधीक्षण अभियन्ता।

आरो पी० सिंह
अधीक्षण अभियन्ता।

आरो पी० सिंह
(ए०पी० सिंह)
संयुक्त सचिव।